



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2012/चैत्र 30, 1934

No. 91]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2012/CHAITRA 30, 1934

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012  
(2012 का 1)

सं. 301-24/2012-ईआर.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप-खण्ड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये आदेश सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची — II में "टैरिफ" शीर्षक के अंतर्गत मद "(6) प्रीपेड सेवा के लिए टैरिफ" में वर्णित प्रविष्टि के परन्तुक में,---

(क) खण्ड (क) के लिए, निम्नलिखित खण्ड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम से कम 10 रुपए मूल्यवर्ग का एक टॉप अप

वाउचर का प्रस्ताव करेगा तथा उसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा";

(ख) खण्ड (एफ) के उप-खण्ड(ii) के लिए, निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) प्रशासनिक लागत या व्ययों के रूप में बीस रुपए से कम अधिकतम खुदरा मूल्य वाले प्रत्येक टॉप अप वाउचर पर दो रुपए तथा बीस रुपए या उससे अधिक वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के प्रत्येक टॉप अप वाउचर पर तीन रुपए से अधिक फीस नहीं लगाई जाएगी” ।

राज पाल, सलाहकार (ईआर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/12]

**टिप्पणी 1 :-** दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306-1/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002

22वां	312-5/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301-56/2003-आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301-2/2004-आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37/2004-आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301-31/2004-आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34/2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301-34/2006-आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18/2007-आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36/2007-आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301-14/2008-आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301-31/2007-आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301-25/2009-आर्थिक दिनांक 20.11.2009

टिप्पणी 2 - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

### व्याख्यात्मक ज्ञापन

वाउचर के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और जमा सेवा कर सहित टॉक वैल्यू के बीच के अंतर को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस निर्धारित शुल्क का उल्लेख करने के लिए विभिन्न नामावलियों का प्रयोग किया जाता है। टीटीओ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश के जरिए अनन्य रूप से टॉक वैल्यू के प्रावधान से संबंधित किसी भी रिवार्ज वाउचर पर प्रोसेसिंग फीस के लिए दो रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी।

2. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 में दोहराया गया है कि टॉप अप वाउचर में प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक कोई भी प्रशासनिक या प्रोसेसिंग फीस शामिल नहीं होगी।

3. भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (एयूएसपीआई) और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर संघ (सीओएआई) ने टॉप अप वाउचर की प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को मौजूदा 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने का अनुरोध किया है। इसके समर्थन में यह तर्क रखा गया है प्राधिकरण द्वारा दो रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित करके बाद से पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। इस संबंध में अपने तर्क के समर्थन में वेतन/मजदूरी में बढ़ोत्तरी, परिवहन और डीजल की कीमतों में वृद्धि, भंडारण सहित अन्य कारणों से सेवा प्रदान करने की लागत बढ़ जाने का उल्लेख किया गया है।

4. सीओएआई और एयूएसपीआई से प्राप्त प्रतिवेदनों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2012 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से संबंधित कतिपय मुद्दों" पर परामर्श पत्र जारी करके हितधारकों से टिप्पणियों मांगी गई। प्रशासनिक और प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा को बढ़ाने से संबंधित मुद्दे पर परामर्श के लिए निम्नलिखित विशेष प्रश्न उठाए गए थे:

- क्या टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने, जैसा कि सेवा प्रदाता संघों ने अनुरोध किया है, के पर्याप्त औचित्य मौजूद हैं?
- यदि हां, तो क्या प्रोसेसिंग फीस में उपरोक्त वृद्धि की अनुमति केवल पेपर वाउचर के संबंध में दी जाएगी?

5. हितधारकों से टिप्पणियां 25 मार्च, 2012 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। एयूएसपीआई, सीओएआई, कुछेक सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता संगठनों और व्यक्तियों से लिखित में टिप्पणियां प्राप्त हुई। हितधारकों की इन टिप्पणियों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:-

6. सेवा प्रदाताओं और उनके संघों ने प्रोसेसिंग फीस को बढ़ाकर 3 रुपए करने के अपने पुराने तर्क को दोहराया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि 2 रुपए की उच्चतम सीमा तीन साल से भी पहले निर्धारित की गई थी और उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि रिचार्ज वाउचरों से संबंधित लागतों की वसूली करने के लिए यह उच्चतम सीमा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दिए गए कारणों में मुद्रास्फीति का दबाव और टीसीपीआर, 2012 में यथा निर्धारित फॉट-साइज और कलर कोड आदि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामग्री की लागत में वृद्धि शामिल हैं। इसके अलावा, वितरण और रिटेल कमीशन, वाउचरों का मुद्रण, वाउचरों के एक्टिवेशन पर एसएमएस एलर्ट से संबंधित लागतों के साथ-साथ एआरपीयू का निम्न स्तर एवं उपभोक्ताओं द्वारा हाई वैल्यू वाले टॉप अप वाउचरों के स्थान पर कम मूल्य वाले टॉप अप वाउचरों को अपनाने जैसे कारणों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। बहरहाल, एक सेवा प्रदाता ने उल्लेख किया है कि 100 रुपए तक के वाउचरों पर 2 रुपए की उच्चतम सीमा जारी रखी जानी चाहिए क्योंकि कम आय वाले एक बड़े वर्ग द्वारा कम मूल्य के वाउचरों का आमतौर पर ज्यादा उपयोग किया जाता है।

7. उपभोक्ता समूहों और व्यक्तियों ने दो रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को जारी रखने के संबंध में अपने-अपने तर्क रखे हैं। ऐसे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं जिनमें टॉप अप वाउचरों

1370 G1/12-2

पर अलग से प्रोसेसिंग फीस की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है। इसके अलावा, कुछ उपभोक्ता समूहों और व्यक्तियों ने यह भी तर्क दिए हैं कि यदि प्रोसेसिंग फीस बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में, कम आय वाले और कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों को प्रोसेसिंग फीस में ऐसी बढ़ोतरी से बाहर रखा जाए। जबकि एक व्यक्ति ने यह उल्लेख किया है कि प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 3 रुपए करना औचित्यपूर्ण है।

8. ऊपर वर्णित परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अपने लिखित सुझावों के अलावा, सीओएआई ने टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि करने के अपने प्रस्ताव को सही ठहराते हुए प्राधिकरण को एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें यह दोहराया गया है कि प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बाद, पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालन लागत में वृद्धि होने के कारण टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि करना अपरिहार्य हो गया है। आगे, टीसीपीआर, 2012 के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यय एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की आय में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। सीओएआई ने तर्क दिया है कि प्रोसेसिंग फीस में प्रस्तावित वृद्धि से केवल टीसीपीआर, 2012 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आय में हुई कमी के एक भाग को पूरा किया जा सकेगा।

9. प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं और उनके संघों द्वारा दिए गए औचित्यों के साथ-साथ एपीआरयू में गिरावट के रुझान को समझता है। सितंबर, 2008 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसएम और सीडीएमए सेवा के लिए प्रीपेड सेवा में एआरपीयू क्रमशः 189 रुपए और 95 रुपए था। दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसएम और सीडीएमए के लिए एआरपीयू कम होकर क्रमशः 81 रुपए और 47 रुपए हो गया है।

10. उपरोक्त औचित्यों के बावजूद, प्राधिकरण महसूस करता है कि प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि का उन उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो आमतौर पर कम मूल्य के टॉप अप वाउचर खरीदते हैं। दूसरी ओर प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा में वृद्धि पर विचार

करते समय यह ध्यान आवश्यक है कि उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है ताकि टॉप अप वाउचरों के जरिए प्रदत्त शुद्ध मौद्रिक मूल्य की तुलना में प्रोसेसिंग फीस वहन करने योग्य स्तर पर बनी रहे। कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों के मामले में प्रोसेसिंग फीस में किसी भी वृद्धि का प्रभाव काफी व्यापक रहेगा। नीचे सारणी में दिए गए विवरण में विभिन्न मूल्य के टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि से पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है:-

अधिकतम खुदरा मूल्य रुपए	12 36 प्रतिशत की दर से सेवा कर + शिक्षा उपकर	प्रोसेसिंग फीस		मौद्रिक मूल्य, अगर पीएफ = 2 रुपए		मौद्रिक मूल्य, अगर पीएफ = 3 रुपए	
		रुपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत	रुपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत	रुपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत
10	1.10	2	20%	6.90	69%	5.90	59%
20	2.20	2	10%	15.80	79%	14.80	74%
30	3.30	2	6.7%	24.70	82%	23.70	79%
40	4.40	2	5%	33.6	84%	32.6	81.5%
50	5.50	2	4%	42.50	85%	41.50	83%
100	11.00	2	2%	87.00	87%	86.00	86%
200	22.00	2	1%	176.00	88%	175.00	87%
500	55.00	2	0.4%	443.00	89%	442.00	88%
1000	110.00	2	0.2%	888.00	89%	887.00	89%

11. 10/-रुपए के वाउचर के मामले में, जो कि उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है, की प्रोसेसिंग फीस 3/-रु० हो जाने से मौद्रिक मूल्य 69 प्रतिशत से घटकर 59 प्रतिशत हो जाएगा अर्थात् बात करने के समय में 10 प्रतिशत की कमी होगी। 20/-रुपए के टॉप अप वाउचरों के मामले में, बात करने के समय के प्रभावी मौद्रिक मूल्य 79 प्रतिशत से घटकर 74 प्रतिशत हो जाएगा (5 प्रतिशत प्वाइंट की कमी) तथा जो आगे भी जारी रहेगी। जबकि उच्च मूल्यवर्गों के टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस का नाममात्र प्रभाव पड़ेगा।

12. प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि के औचित्यों के समर्थन का मूल्यांकन करते हुए प्राधिकरण यह भी महसूस करता है कि बीस रुपए से कम के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले वाउचरों को

प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि से बाहर रखा जाए। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि प्रोसेसिंग फीस की निर्धारित राशि का प्रभाव अधिक मूल्य के टॉप अप वाउचरों की तुलना में कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों पर अधिक पड़ेगा। मल्टीपल रिचार्ज के साथ उपभोक्ता कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों के साथ अधिक रिचार्ज करा रहे हैं और इस प्रकार वे अधिक मूल्य के टॉप अप वाउचर के साथ रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। अतः टॉप अप वाउचरों के सभी मूल्यों में एक समान निर्धारित प्रोसेसिंग फीस रखना समानता की भावना के विपरीत प्रतीत होता है।

13. इसके अलावा, प्राधिकरण पेपर टॉप अप वाउचरों और इलेक्ट्रॉनिक वाउचरों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस पर एक समान उच्चतम सीमा के संबंध में सेवा प्रदाताओं और उनके संघों के सुझावों से सहमत है। पेपर टॉप अप के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक टॉप अप वाउचरों पर एक समान प्रोसेसिंग फीस पारदर्शिता और समानता के परिप्रेक्ष्य में भी उपयुक्त रहेगी।

14. अतः प्राधिकरण ने बीस रुपए या उससे अधिक वाले अधिकतम खुदरा मूल्य वाले टॉप अप वाउचरों के संबंध में, टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को दो रुपए से बढ़ाकर तीन रुपए करने और बीस रुपए से कम के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले टॉप अप वाउचरों के संबंध में दो रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया है।

15. इससे संबंधित एक और मुद्दा, बाजार में कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ा है क्योंकि ऐसे टॉप अप वाउचरों की अनुपलब्धता के मामले, प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हैं। अतः उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के दृष्टि से, प्राधिकरण आदेश देता है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता कम से कम 10 रुपए मूल्यवर्ग का एक टॉप अप वाउचर का प्रस्ताव करेगा तथा उसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।



**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2012

**The Telecommunication Tariff (Fiftieth-Amendment) Order, 2012**  
**(No. 1 of 2012)**

**No. 301-24/2012-ER.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fiftieth amendment) Order, 2012.

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II of the Telecommunication Tariff Order, 1999, under the heading "Tariff", in the entries appearing against the item "(6) Tariff for prepaid service", in the proviso, ---

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Every service provider shall offer and make available to the consumer at least one top up voucher, of denomination of rupees ten.";

(b) for sub-clause (ii) of clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) a nominal fee, not exceeding two rupees for each top up voucher having maximum retail price below rupees twenty and not exceeding three rupees for each top up voucher having maximum retail price of rupees twenty or more, shall be levied towards administrative cost or expenses."

RAJ PAL, Advisor (ER)

[ADVT. III/4/Exty./142/12]

1370 GI/12-3

**Note 1:-** The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9<sup>th</sup> March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date
1 <sup>st</sup>	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 <sup>nd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3 <sup>rd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 <sup>th</sup>	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 <sup>th</sup>	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13 <sup>th</sup>	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14 <sup>th</sup>	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 <sup>th</sup>	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17 <sup>th</sup>	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 <sup>th</sup>	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21 <sup>st</sup>	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 <sup>nd</sup>	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23 <sup>rd</sup>	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 <sup>th</sup>	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003

28 <sup>th</sup>	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 <sup>th</sup>	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 <sup>th</sup>	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31 <sup>st</sup>	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 <sup>nd</sup>	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33 <sup>rd</sup>	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41 <sup>st</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 <sup>nd</sup>	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 <sup>rd</sup>	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 <sup>th</sup>	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 <sup>th</sup>	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 <sup>th</sup>	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 <sup>th</sup>	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 <sup>th</sup>	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 <sup>th</sup>	No. 301-25/2009-ER dated 20.11.2009

Note 2. – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fiftieth Amendment) Order, 2012.

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The difference between the Maximum Retail Price (MRP) of the vouchers and the talk value plus service tax is known as processing fee, though different nomenclatures are used to refer to this fixed charge. Through TTO (Forty-Eighth Amendment) Order a ceiling of rupees two was prescribed on processing fee on any recharge voucher exclusively meant for provision of talk value.

2. The Telecom Consumers Protection Regulations (TCPR), 2012 reiterate that Top up voucher shall not contain any administrative or processing fee beyond the ceiling specified by the Authority.

3. Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI) and Cellular Operators Association of India (COAI) have requested for upward revision of the Processing Fee in Top up vouchers to rupees three from the existing ceiling of rupees two. It has been argued that there has been inflationary pressure in the last three years since the ceiling of rupees two was prescribed by the Authority. Cost of providing service by way of hike in salaries/wages, increase in cost of transportation & diesel cost, increase in cost of storage etc., among others have been cited as supporting arguments in this regard.

4. In order to decide on above representations from COAI and AUSPI, the Authority has invited comments of the stakeholders by issuing a consultation paper on "Certain issues relating to the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012" on 15<sup>th</sup> March, 2012. On the issue of increasing ceiling on administrative and processing fee, the following specific questions were raised for consultation:

- **Is there sufficient justification to increase the ceiling on processing fee on Top up vouchers from Rs.2/ to Rs. 3/-, as requested by the associations of service providers?**

- **If yes, should the above increase in processing fee be allowed only in respect of paper voucher?**

5. The stakeholders were requested to send their comments by the 25<sup>th</sup> March 2012. Written comments have been received from AUSPI, COAI, few service providers, consumer organisations and individuals. These comments of the stakeholders are briefly discussed as under:

6. The service providers and their associations have reiterated their stated position arguing for increase in the Processing Fee to Rs.3/-. It has been argued that the ceiling of Rs 2/- was prescribed more than three years ago and even at that time they had submitted that the ceiling was not sufficient to recover costs related to recharge vouchers. The reasons given are inflationary pressures and increase in cost of the material to meet requirements of font-size and colour code etc. as prescribed by TCPR, 2012. In addition, the costs relating to the distribution and retail commission, printing of vouchers, SMS alerts on activation of vouchers as well as the low level of ARPU and customers moving away from high value top up vouchers to small denomination top up vouchers have been highlighted. However, one service provider has stated that the ceiling of Rs.2/- should continue on denominations up to Rs.100/- as lower denominations are generally used by low income strata.

7. The consumer groups as well as individuals have argued for continuation of the existing ceiling of rupees two. There are also suggestions for not allowing any separate processing fee on top-up vouchers. Further, some of the consumers groups and individuals have argued that in case the ceiling on processing is increased, the top up vouchers of smaller denominations should be exempted from such hike in processing fee in order to protect interests of marginal and low usage subscribers. While one individual has stated that the increase in ceiling on processing fee to Rs. 3/- is justified.

1370 42/12-4

8. Subsequently, in addition to their written suggestions in response to the above cited consultation paper, COAI have submitted another representation to the Authority justifying their proposal for increase in processing fee on top up vouchers. It has been reiterated that the upward revision of processing fee on top up vouchers is inescapable on account of increase in operating costs over the years since the ceiling on processing fee was prescribed. Further, the costs arising out of the implementation of the TCPR, 2012 and drop in revenue of the telecom service providers have also been highlighted. COAI have also argued that the proposed increase in processing fee will only mitigate a portion of the revenue shortfall that has been witnessed with implementation of the TCPR.

9. The Authority appreciates the justifications given by the service providers and their associations as well as the falling trend in APRU. The ARPU in respect of prepaid service for GSM and CDMA was Rs.189 and Rs.95 respectively for the quarter ending September 2008. The ARPU for GSM and CDMA for the quarter ending December 2011 have fallen to Rs.81 and Rs.47 respectively.

10. Notwithstanding the above justifications, the Authority feels that hike in the Processing Fee is likely to adversely impact the users who generally buy Top up vouchers with smaller denominations. While considering increase in the existing ceiling on processing fee, it is necessary to see how the interest of users can be protected so that the processing fee remains at affordable level vis-a-vis the net monetary value offered through the Top up voucher. The impact of any increase in the Processing Fee will be much more in the case of lower denominations Top up vouchers. Details given in the Table below illustrate the extent of impact on of processing fee on top up vouchers of various denominations:

MRP Rs.	Service Tax + Education cess @ 12.36%	Processing Fee		Monitory Value if PF = Rs. 2		Monitory Value if PF = Rs. 3	
		Rs.	%age of MRP	Rs.	%age of MRP	Rs.	%age of MRP
10	1.10	2	20%	6.90	69%	5.90	59%
20	2.20	2	10%	15.80	79%	14.80	74%
30	3.30	2	6.7%	24.70	82%	23.70	79%
40	4.40	2	5%	33.6	84%	32.6	81.5%
50	5.50	2	4%	42.50	85%	41.50	83%
100	11.00	2	2%	87.00	87%	86.00	86%
200	22.00	2	1%	176.00	88%	175.00	87%
500	55.00	2	0.4%	443.00	89%	442.00	88%
1000	110.00	2	0.2%	888.00	89%	887.00	89%

11. In the case of Rs.10/- voucher, which is very popular among users, the monetary value will be reduced to 59% from 69% with increase in processing fee to Rs.3/- i.e., 10% reduction in talk time. In the case of Rs.20 Top up vouchers, effective talk-time value will get reduced to 74% from 79% (reduction of 5 %age points), and so on. As such, for higher denominations of Top up vouchers, the impact of Processing Fee is minimal.

12. While appreciating the justifications in support of increase in processing fee, the Authority feels that the top up vouchers having MRP less than rupees twenty should be exempted from increase in processing fee. The Authority has also noted that the impact of fixed amount of Processing Fee is relatively more on top up vouchers of smaller denominations as compared to higher

denomination top up vouchers. With multiple recharges, the subscribers recharging with smaller denomination top up vouchers end up paying proportionately more processing fee in comparison to the subscribers charging with high value top up vouchers. Therefore, having a uniform fixed Processing Fee across all denomination of Top up vouchers appears to go against equity.

13. Further, the Authority also agrees with the suggestions of the service providers and their association for having a uniform ceiling on processing fee in respect of paper top up vouchers and electronic top up vouchers. A uniform processing fee on paper as well as electronic top up vouchers would be appropriate from transparency and equity perspective.

14. **Therefore, the Authority has decided to increase the ceiling on Processing Fee on Top up vouchers to rupees three from rupees two in respect of Top up vouchers having Maximum Retail Price of rupees twenty and above and to continue with the existing ceiling of rupees two in respect of Top up vouchers having Maximum Retail Price of less than rupees twenty.**

15. Another closely linked issue is ensuring the actual availability of Top up vouchers of lower denominations in the market, as instances of non-availability of such Top up vouchers have been brought to the notice of the Authority. Therefore, with a view to protect the interests of users, **the Authority mandates that every service provider shall offer and make available to the consumer at least one top up voucher, of denomination of rupees ten.**

\*\*\*\*\*